



कल तक 5 2 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने की बात थी

आज चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा बढ़ाकर 68 लाख कर दिया है

- रेणु मिश्रल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 24 जुलाई। इंडिया गठबंधन मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रोशित है, और ऐसे में बिहार का एस आई आर (स्पेशल इन्टैसिव रिबीज़न) मुद्दा आने वाले दिनों में संसद में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इंडिया गठबंधन चाहता है कि कांग्रेस केन्द्र सरकार पर दबाव डाले कि वह इस सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा कराए। लेकिन सूत्रों का कहना है कि गैर-सरकारी माध्यमों एवं चैनलों के ज़रिए सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि वह इस पर चर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार इस मामले में शामिल ही नहीं है। पूरा मामला चुनाव आयोग से जुड़ा है, जो एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, और सरकार इसके लिए न तो ज़िम्मेदार है और न ही जाबदेदा।

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनावों का बहिष्कार करने का सुझाव दिया है, लेकिन इस पर अंतिम

- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में विजयी एनडीए व महागठबंधन में कुल सोलह लाख वोटों का अंतर था।
- विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता का कहना है, अगर विपक्ष ने यह मुद्दा पुरजोर ढंग से अभी नहीं उठाया तो चुनाव आयोग मतदाता सूची से नाम काटने का परीक्षण आसाम, पश्चिमी बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में दोहरायेगा।
- अतः कांग्रेस के सहयोगी दलों के नेताओं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आदि के दिलों को काफी उद्देलित कर रहा है।
- सरकार की सोच है कि अगर विपक्ष को कुछ शिकायत व आशंका है तो विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट/चुनाव आयोग के समक्ष जाना चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, किसी भी तरह से सरकार के अधीन काम नहीं करता। अतः सरकार किसी भी तरह चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

फ़ैसला इंडिया गठबंधन को सामूहिक रूप से लेना होगा और इसमें अभी समय

जो बात विपक्ष के लिए चिंता का विषय बन गई है, वह यह है कि कल चुनाव आयोग ने इससे प्रभावित मतदाताओं की संख्या 52 लाख बताई थी, लेकिन यह आज बढ़कर 68 लाख हो गई है। इस आंकड़े में वे लोग शामिल हैं, जो स्थानांतरित हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, जिनके नाम दो जगह हैं, आदि-आदि।

पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को मिले वोटों में मात्र 16 लाख का अंतर था, ऐसे में 68 लाख वोटों को हटाए जाने की बात विपक्ष के लिए वास्तव में बेहद गंभीर और खतरनाक है।

एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर हम इस मुद्दे पर जोर नहीं देते हैं, तो मोदी और शाह की हिम्मत बढ़ेगी और वे अन्य राज्यों, जैसे असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, में यही रणनीति अपनाएंगे।

यही कारण है कि कांग्रेस के कई सहयोगी, जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीसलपुर बाँध का एक गेट खुला

टोंक, 24 जुलाई। राजस्थान में स्थित बीसलपुर डैम के कैचमेंट एरिया में भारी वर्षा के कारण पर्याप्त पानी भर गया है और अब यह डैम नीचे की ओर पानी छोड़ रहा है। पिछले 21 वर्षों में पहली बार जुलाई के महीने में डैम के गेट खोले गए हैं, क्योंकि जल स्तर बहुत अधिक हो गया है। पानी का स्तर 315.50 आर.एल. मीटर तक पहुँच गया, जिसके बाद जल निकासी के लिए गेट नंबर 10 को एक मीटर खोलकर 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई

- आमजन से नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की गई है।

है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि बीसलपुर बांध पेयजल के लिए जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले के लोगों के लिए लाइफ लाइन है। बीसलपुर सहित, जिले के अन्य लघु, वृहद् एवं मध्यम बांधों में भी पानी की अच्छी आवक होने से लोगों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा तथा क्षेत्र में अच्छी फसल का उत्पादन होगा। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने आमजन से अपील की है कि नदी के बहाव क्षेत्र में नहीं जाएं।

भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स से 2030 तक व्यापार दोगुना होगा

इस एग्रीमेंट के तहत भारत का ब्रिटेन को निर्यात किया जाने वाला 99 प्रतिशत सामान “इयूटी फ्री” प्रवेश करेगा, जिससे टैक्सटाइल, जैम्स व ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स आदि सैक्टर को भारी बढ़ावा मिलेगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के उदारीकरण के बाद के इतिहास में सबसे परिवर्तनकारी व्यापार समझौतों में से एक पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए), जो वर्षों से प्रक्रिया में था, में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, शुल्क बाधाओं को समाप्त करने और नई दिल्ली और लंदन के बीच आर्थिक संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

इसका आर्थिक प्रभाव चौंकाने वाला है। वर्तमान में लगभग 60 अरब डॉलर के आसपास रहने वाला द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। ब्रिटेन को इससे हर साल 25.5 अरब पाउण्ड का लाभ होने का अनुमान है, जबकि भारतीय निर्यात और सेवा प्रदाता प्रमुख क्षेत्रों में

- भारत में भी ब्रिटेन से आयातित जाने-माने सामान, स्कॉच व्हिस्की, जिन पर 150 प्रतिशत रेट से इयूटी लग रही थी, अब घटाकर 75 प्रतिशत कर देगा तथा अगले दशक तक यह “इम्पोर्ट इयूटी” 40 प्रतिशत हो जायेगी।
- इस प्रकार भारत द्वारा ब्रिटेन से आयातित लगज़री कारें, जैसे जैगुआर व लैंडरोवर, पर इम्पोर्ट इयूटी 100 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी जायेगी।
- भारत के सर्विस सैक्टर को भी फ्री प्रवेश मिलेगा ब्रिटेन में। आईटी कंपनियों, फायनैंशियल सर्विसेज़, एजुकेशन, कंसल्टैंसी फर्म आदि को भी ब्रिटेन में काम करने की आज़ादी मिलेगी। अब तक भारतीय प्रोफेशनल्स के समक्ष ब्रिटेन के सोशल सिक्युरिटी पैमेंट की भारी समस्या थी। ब्रिटेन ने इन प्रोफेशनल्स को छूट देने की घोषणा भी की है, कि पहले तीन साल उन्हें सोशल सिक्युरिटी के लिये कुछ योगदान करने का बंधन नहीं रहेगा।

महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। दोनों देशों के अधिकारियों द्वारा इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। यह

समझौता केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह दो सबसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘क्या मृत मतदाताओं को भी वोटर लिस्ट में बने रहने दिया जाए?’

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का विरोध कर रहे विपक्ष से जवाबी सवाल किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 24 जुलाई। सर्वोच्च न्यायालय में 28 जुलाई को मामला पहुंचने से पहले ही, मुख्य चुनाव आयुक्त (सी.ई.सी.) ज्ञानेश कुमार ने आज अपने पक्ष में मजबूती से दलील दी और बिहार में होने वाले चुनाव से पहले मतदाता सूची की स्पेशल इन्टैसिव रिविजन (एस.आई.आर.) के कदम का जोरदार बचाव किया।

पेरशान दिख रहे ज्ञानेश कुमार ने पूछा, “क्या चुनाव आयोग मृत लोगों को मतदाता सूची में रहने दे?” विदित है कि ज्ञानेश कुमार अपने कार्यकाल में अब तक विपक्ष के लगातार आरोपों और चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोपों से जूझते रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा करने के आयोग के कदम के पक्ष में तर्क दिए।

- इस केस पर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता पुनरीक्षण का तगड़ा बचाव किया।
- विपक्ष के सवालों से घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्षी दलों पर कई सवाल दागे, कि क्या दोहरी वोटर आईडी वालों को वोटर लिस्ट में रखा जाना चाहिए, क्या विदेशी प्रवासियों को वोटर लिस्ट में रहने देना चाहिए?
- चुनाव आयोग द्वारा जारी डेटा के अनुसार, बिहार की वोटर लिस्ट से 56 लाख नाम हटाए जाएंगे, इनमें से 20 लाख मृत हैं, 28 लाख मतदाता अन्य राज्यों में हैं, 7 लाख का नाम एक से ज्यादा स्थानों पर रजिस्टर्ड हैं और एक लाख से मतदाताओं से सम्पर्क नहीं हो पाया है।

मुख्य चुनाव आयोग ने सवाल किया, “जिन लोगों के पास डुप्लिकेट ई.पी.आई.सी. (इलेक्टर्स फोटी आईडेंटिटी कार्ड) हैं, क्या उन्हें रहने देना चाहिए? क्या विदेशी नागरिकों को

मतदाता सूची में होना चाहिए? फिर विरोध किस बात का है?”- उन्होंने जोर देकर कहा कि एक शुद्ध और पवित्र मतदाता सूची ही एक सफल लोकतंत्र की नींव होती है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग का देह शोषण करने वाले अभियुक्तों को 20 साल की सजा

जयपुर, 24 जुलाई। जिले की पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को डरा धमकाकर उसका कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त शैतान और रविन्द्र को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल चार लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवांसिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने पीड़िता

- शोषण से पीड़ित युवती ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की थी।

के साथ कई बार दुष्कर्म कर नैतिक रूप से अकल्पनीय अपराध किया है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 31 मार्च, 2022 को पीड़िता के पिता ने जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी बेटी ने उसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा से नाराज़ हिंदू वोटों पर नज़र है अखिलेश की

इस वोट बैंक को रिझाने के लिए अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं

- सावन मास में हर सोमवार वे सैफई गाँव में स्वयं द्वारा बनवाए जा रहे शिव मंदिर का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, इस मंदिर का नाम उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के नाम पर केदारेश्वर धाम रखा गया है।
- मंदिर के नाम को लेकर भारी विवाद छिड़ गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने इसे सनातन धर्म के खिलाफ अखिलेश की साजिश बताया।
- अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो स्वयं को हिंदुत्व का सबसे ताकतवर “आईकन” मानते हैं।

प्रतीकों का प्रयोग उन हिंदू मतदाताओं को आकर्षित कर पाएगा, जिनका भाजपा से मोह भंग हो गया है, तथा इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम-यादव वोटबैंक उनके साथ बना रहेगा।

2024 के लोकसभा चुनावों में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी) फॉर्मूले की सफलता

ने अखिलेश यादव को यह विश्वास दिला दिया है कि वे अपनी राजनैतिक पहुंच को अपनी पारम्परिक सीमा से आगे ले जा सकते हैं।

‘सॉफ्ट हिन्दुत्व’ में उनके प्रवेश की कोशिश हाल ही में साफ तौर पर दिखाई दी है तथा सावन के पवित्र महीने में उनकी इन कोशिशों ने और गति पकड़ ली है। वे सावन के हर सोमवार (जो

भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है), जो शिव मंदिर से संबंधित वीडियो साझा कर रहे हैं।

ये वीडियो किसी अन्य मंदिर के नहीं, बल्कि उसी मंदिर के हैं, जिसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा इटावा जिले के लुहना गांव में, उनके पैतृक स्थान सैफई के पास, बनवाया जा रहा है।

जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में यादव समुदाय के जलाभिषेक कार्यक्रम में उनकी गैरहाज़िरी के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है, वहीं यह समझा जा रहा है कि वे भाजपा की हिंदुत्व शैली में ढलने की बजाय, अपनी एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाना चाहते हैं।

यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि काशी कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है और मंदिर के पुनरुद्धार को मोदी की धार्मिक विरासत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज निर्णय होगा उदयपुर फाइल्स रिलीज़ पर

नयी दिल्ली, 24 जुलाई। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या पर बनी हिंदी फिल्म उदयपुर फाइल्स पर अंतरिम रोक जारी रहनी चाहिए या नहीं, उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर शुक्रवार को संक्षिप्त सुनवाई के बाद आदेश पारित करेगा।

- उदयपुर फाइल्स पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है।

पूर्वक सुनने के बाद कहा कि कल इस मामले का निपटारा किया जायेगा।

फिल्म के निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के फिल्म का प्रदर्शन शुरू होने में हो रही देरी के विरोध पर पीठ ने कहा, आपने सही इंतज़ार किया है, क्योंकि कानून यही चाहता है। मुद्दा यह है कि क्या (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

जब पैसा बोलता है तब सत्य मौन रहता है। –कहावत

हम देश के नागरिक यह स्वीकार नहीं करेंगे कि विदेशी फर्जी मतदाता भारत के भाग्य विधाता बने

बिहार में निकट भविष्य में चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव अक्टूबर-नवम्बर में हैं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक उचित जाँच के बाद लोगों के नाम जो मतदान करने के अधिकारी पाये गये उनके नाम 30 सितम्बर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से हटा दिये जावेंगे। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अपडेट (Update) करने के तथा अवैध तथाकथित मतदाताओं को हटाने के लिये शुरू की गई है।

अधिकारियों द्वारा गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान यह पाया गया है नेपाल, बांग्लादेश व म्यांमार के सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं और इनके पास आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसे कई प्रकार के पहचान पत्र हैं ये कागजात गलत तरीके से प्राप्त किये गये हैं। अत: इनके नाम 30 सितम्बर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची से हटा दिये जावेंगे। अधिकारीगण बूथ लेवल पर घर-2 गये हैं और उन्होंने जांच की है। आयोग को सूचना के आधार पर यह भी जानकारी उपलब्ध है कि 80.11: मतदाता (करीब 6.32 करोड़) ने अपने ईएफ (एन्युमरेशन फार्म) जमा करा दिये हैं। 18 लाख मृत वोटर्स पाये गये। 7 लाख वोटर्स का नाम तो जगह दर्ज है। ताजा समाचार के अनुसार 97: काम पूरा हो चुका है।

चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पूर्व यह स्पष्ट किया है कि बिहार की तरह सभी राज्यों की विधान सभाओं की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण होगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि उनका पूरा प्रयत्न होगा कि देश की मतदाता सूची में एक भी विदेशी नागरिक नहीं रहना चाहिये।

बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा चल रही है जो एक वैधानिक प्रक्रिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय खण्डपीठ के समक्ष इस प्रक्रिया की वैधानिकता को कई रिट् याचिकाओं में चुनौती दी है। सुनवाई के समय इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की प्रार्थना पिटीशनरों की ओर से की गई थी; किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने यह कहकर प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि चुनाव आयोग वैधानिक संस्था है और उसके कार्य को रोकना जाना कोर्ट उचित नहीं समझ रही है।

माननीय कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों की बहस चल रही है जिसमें कई संवैधानिक व वैधानिक प्रश्न उठाये गये हैं। स्वतंत्र, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से मतदाता सूचियों की शुद्धिकरण किया जाना चुनाव आयोग का दायित्व है। पिटीशनर्स की ओर से उक्त प्रक्रिया के विरुद्ध कानूनी आपत्तियां उठाई गई हैं। एक आपत्ति यह उठाई गई है कि जब मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम है जो पहले भी वोट दे चुका है तो उसे मतदान करने से नहीं रोका जा सकता। यह भी आपत्ति की जा रही है कि अधिकारीगण जाँच घर-2 जाकर नहीं कर रहे हैं ऑन लाईन फार्म के लिये अवैध वसूली हो रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसे महाराष्ट्र की तर्ज पर चोरी या चुनाव चोरी की कोशिश बताया है। राजव के नेता तेजस्वी यादव और सांसद पप्पू यादव ने इसे गरीब दलित व प्रवासी मजदूरों के वोटिंग अधिकारों को छीनने का कोशिश माना है। कई लोगों का कहना है कि अभिप्राय मतदाता सूची को शुद्धता का नहीं है अपितु सत्ताखंड एनडीए को लाभ पहुंचाने का है।

मूल बहस जो चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है वह दो बिन्दुओं पर केन्द्रित है। प्रथम चुनाव आयोग के अधिकार पर जो उसे संविधान ने अनुच्छेद 324(1) के माध्यम से दिये हैं। दूसरा बिन्दु है मताधिकार का आधार जो केवल भारत के नागरिक को ही प्राप्त है। इसका पूर्ण विवेचन संविधान के अनुच्छेद 326 में किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार निर्वाचन के अधीक्षण (uperintendence), निर्देशन (Direction) व नियंत्रण (Control) चुनाव आयोग में निहित है। अनुच्छेद 324(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का ओर उन सभी के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण एक आयोग में निहित होगा जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग (Election Commission) कहा गया है।

इसका अभिप्राय है चुनाव आयोग को चुनाव कराने, निर्वाचक नामावली (Electoral Rolls) बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है अर्थात् निर्वाचन (Election) के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार है। इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में माना है कि चुनाव आयोग को चुनावों के सम्बन्ध में न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका के अधिकार प्राप्त हैं।

हमें यहाँ तो स्वीकार करना ही होगा कि चुनाव आयोग संविधान के तहत चुनावों की प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में एक संवैधानिक संस्था है और नागरिक होने के कारण उनका यह मूल कर्तव्य है कि वे इस संस्था का सम्मान करें आदर करें। संविधान के अनुच्छेद 51(क) में स्पष्ट घोषणा है कि “भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं का आदर करे”।

चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर रहा है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक हैं या नहीं। अर्थात् संविधन के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर रहा है कि वे लोग जो दूसरे देशों के नागरिक मतदाता के तौर पर मिले हैं क्या वे भारत के नागरिक हैं? बूथ स्तर के मतदाता को पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के हजारों लोगों का पता चला है। उनके पास आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट राशन कार्ड भी मिले हैं।

किन्तु भारत की राजनीति में संस्थाओं के प्रति आदर कहीं खो गया है।

यह सही प्रतीत होता है कि नागरिकता के बाबत निर्णय करने का अधिकार केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। चुनाव आयोग केवल यह परीक्षण कर रहा है कि मतदाता क्या भारत का नागरिक है या नहीं। अर्थात् संविधान के भाग-2 में दिये गये आधारों पर परीक्षण कर रहा है कि वे लोग जो दूसरे देशों के नागरिक मतदाता के तौर पर मिले हैं क्या वे भारत के नागरिक हैं? बूथ स्तर के मतदाता को पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के हजारों लोगों का पता चला है। उनके पास आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट राशन कार्ड भी मिले हैं। आपत्ति केवल यह है कि वे संविधान के भाग-2 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार भारत

के नागरिक नहीं हैं। संविधान के अनुसार मतदान को अधिकार केवल भारत के नागरिक को है। इस विषय पर चर्चा के लिये, आईये, हम यह जाने कि संविधान के भाग-2 के अनुवसर भारत का नागरिक कौन हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत भारत की संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन किया है। कानून है नागरिकता अधिनियम, 1955 और दूसरा के नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीसीए)।

भारत की नागरिकता निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होती है:-

(1) जन्म से नागरिकता - 26 जनवरी 1950 में 01.07.1987 के मध्य भारत में पैदा हुये व्यक्ति। 1 जुलाई 1987 से 12 दिसम्बर 2024 के बीच जन्मे व्यक्ति के माता-पिता में से कम से कम एक एक भारतीय हो। 06.12.2024 के बाद जन्मे होने पर एक माता-पिता भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिये।

(2) वंश के आधार पर - यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ हो, लेकिन उसके माता-पिता भारत के नागरिक हैं तो वह पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले सकता है।

(3) पंजीकरण द्वारा - भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत के विवाहित विदेशी नागरिक या जो कुछ वर्षों से भारत में रह रहे हों वे आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।

(4) By Naturalization (विदेशी) जो भारत में 12 वर्षों से रह रहे हैं (11 वर्ष आवेदन से ठीक पहले 1 वर्ष)

(5) राज्य के भारत में विलय के कारण।

इससे स्पष्ट होगा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा वोटर लिस्ट में नाम होने मात्र से वह व्यक्ति भारत देश का नागरिक नहीं हो सकता। नागरिक संशोधन अधिनियम, 2019 व उसके नियम बिहार के उपरोक्त तथाकथित मतदाताओं पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व भारत आये हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्राप्त करने के लिये प्राकृतिककरण की अवधि 11 से घटाकर 5 वर्ष करता है।

रिट् याचिकायें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ में जेरकार हैं और जिनमें माननीय न्यायालय गम्भीरता से दोनों पक्षों की बहस सुन रहा है, कानून की स्थिति के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को है और वह भारत का नागरिक, संविधान तथा नागरिकता अधिनियम के दिये गये मानदण्डों के अनुसार नागरिक है। चुनाव आयोग आपत्ति कर रहा है कि बिहार के वे तथाकथित मतदाता तथा जो बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के लोग हैं, उन्हें वह मतदाता अर्थात् भारत देश में मतदान करने का अधिकारी नहीं मानता। हाँ, यदि वे कुछ मांगे गये दस्तावेजात पेश करें और संतोष करा दे तो वह आपत्ति उठा लेगा या वे नागरिकता के मामले को नियमों के अनुसार गृह मंत्रालय से तय करा लेवें और सर्टिफिकेट प्राप्त करलें कि वे भारत के नागरिक हैं उन्हें देश का नागरिक मान लेना और मतदान का अधिकारी मानकर मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो जावेगा।

दूसरा प्रश्न और भी है वह है Estoppel keâe efkeâvleg Estoppel का नियम कानून के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता।

बहस के दौरान यह सभी पक्षों ने माना है कि मतदान का अधिकार केवल देश का नागरिक ही को है। जो व्यक्ति (मतदाता) अपना नाम वोटर लिस्ट में बतलाने अथवा आधार कार्ड व राशन कार्ड उनके नाम होने के कारण अपने को मतदान का अधिकारी मानता है, उसकी वैधता बाबत जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। उसे गृह विभाग के मंत्रालय से प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा।

इस विवाद का एक पहलु और भी है। हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में रिट् याचिका दायर करने का अधिकार केवल मात्र देश के नागरिक को है अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को है। प्रस्तुत केस तथाकथित मतदाताओं में से किसी ने दायर नहीं किया है। अत: यह प्रश्न भी माननीय कोर्ट के समक्ष रखना चाहिये कि याचिकायें सुनवाई के योग्य ही नहीं हैं। सिक्किम के भारत में विलय को लेकर सिक्किम के पूर्व शासक विलय की वैधता को सिक्किम हाईकोर्ट में चुनौती दी, उस समय जस्टिस श्रीमाल एण एल सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। केस उनकी पीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्रीमाल ने आपत्ति की थी कि भारत का नागरिक ही रिट् याचिका पेश कर सकता है, अन्य नहीं। सुनवाई उसी समय की जावेगी जब पिटीशनर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि वह भारत का नागरिक है। शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ। सिक्किम बिहार का अभिन्न अंग हो गया।

देश इसे स्वीकार नहीं करेगा कि विदेशी फर्जी मतदाता भारत का भाग्य विधाता बने। सबको सम्पत्ति दे भगवान!

–**अतिथि सम्पादक,**
पानाचन्द्र जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

हरियालो राजस्थान: हरित समृद्धि की ओर ले जाने का मुख्यमंत्री का संकल्प



रचना सिद्धा

आज विश्व अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। इन समस्याओं में से एक बहुत बड़ी समस्या है प्राणी और वनस्पति जगत के बीच का असंतुलन। आबादी की बेतहाशा बढ़ोतरी और प्राकृतिक संसाधनों पर हमारी बढ़ती निर्भरता ने इस संतुलन को बिगाड़ा है जिससे हमारे सामने आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल के कटते रहने से मानव सभ्यता को ही खतरा पैदा हो गया है। मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। धरती के कुछ भाग या तो सालों तक सूखे रहते हैं या फिर वहां भयानक बाढ़ आ जाती है। पहाड़ों में भूस्खलन और ग्लेशियर का पिघलना भी प्रकृति के इसी अतिदोहन का परिणाम है। वन और पानी किसी भी समाज के लिए सबसे आवश्यक हैं। अगर ये विलुप्त हो जाएं त्राहिमाम मच जाए और सभ्यता का विनाश हो जाए।

जीवन की दृष्टि से पर्यावरण मानव के लिए सर्वोच्च जरूरत है। जल, जंगल और जमीन तीनों उसके प्रमुख आधार हैं। लेकिन आधुनिकता और विलासिता की दौड़ और सबसे आगे निकल जाने की लालच में बढ़ते प्रदूषण ने जीवन के इन तीनों आधारों

को हमसे छीन लिया है जो कि हमारे आधुनिक और सभ्य कहे जाने वाले समाज की एक बहुत बड़ी विफलता है। यही वजह है कि आज देश की आबादी का बड़ा हिस्सा स्वच्छ और सुरक्षित पानी, शौचालय तथा शुद्ध हवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। पर्यावरण पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। इस दिशा में समाज और सरकार को स्वच्छता और वृक्षारोपण को एक जनान्दोलन बनाने की तरफ सोचना होगा जिसके लिए समाज की सहभागिता होना पहली और आवश्यक शर्त है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को बहुत गंभीरता से लेते हुए वृक्षारोपण को बहुत महत्वपूर्ण बताया। अपने मन की बात में प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लोगों से अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करते हुए नई दिल्ली के बुद्ध पार्क में पीपल का एक पौधा लगाया। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी मां के साथ मिलकर अथवा उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। यह पेड़ उनकी तरफ से उनके लिए एक अनमोल उपहार होगा।

प्रधानमंत्री के इस अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने को संकल्पित मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पिछले वर्ष 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर दूदू जिले के गहोता में पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान का विधिवत शुभारंभ किया और पांच वर्षों में राज्य में 50 करोड़ तथा वर्ष

2024-25 में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया।

हरियालो राजस्थान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को हरा भरा बनाने और वन क्षेत्र का विस्तार करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन बनाए रखना है। इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण तथा वन्यजीवों के लिए बेहतर पारिस्थिति की तंत्र तैयार करने में स्थानीय समुदायों की जागरूकता बढ़ाते हुए अभियान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर पौधारोपण को जन आंदोलन बनाना भी हरियालो राजस्थान का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सरकार ने पांच वर्षों में राज्य में पचास करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर प्रदेश में अभियान के पहले चरण में प्रदेश में सात करोड़ पौधे लगाए गए जिसका वर्ल्ड रिकार्ड भी बना। अभियान की आगे बढ़ाते हुए अब हरियालो राजस्थान के दूसरे चरण में दस करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं और कई तरह के नवाचार भी किए जा रहे हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए हरियालो राजस्थान नामक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है। लगाए गए हर पौधे की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिएइस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की व्यवस्था की गई है।

इस अभियान ने नवाचार, आधुनिक तकनीक और जन सहभागिता के माध्यम से जनआंदोलन का रूप ले लिया है। इसी क्रम में नदियों के किनारों, औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के आसपास, विद्यालयों, अस्पतालों तथा नगरीय क्षेत्रों में पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इस अभियान में सामाजिक संगठनों,



शैक्षणिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इनके माध्यम से अभियान को जनसामान्य से जोड़ा गया और यह अभियान महज एक सरकारी कार्यक्रम न होकर जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हर जिले में आमजन की भागीदारी से मातृवन बनाए जा रहे हैं जहां नागरिक अपने परिवारों की स्मृति में वृक्ष लगाकर प्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

आज हम जिस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं उसके पीछे वनों को कटाई एक प्रमुख कारण है। इसके कारण पिछले कुछ समय में मानव जाति को कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री ने जिस अभियान की शुरुआत कर दी है वह न केवल वनों और हमारे पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करेगा बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण भी तैयार करेगा। लेकिन यहां बहुत ध्यान रखने की बात यह भी है कि जो पौधे या पेड़

लगाए जा रहे हैं उनकी देखभाल कितने समय तक की जाती है। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किनको दी जाती है। क्योंकि यहां आंकड़े दिखाते भर के लिए पौधे लगाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 200 पेड़ लगाने वाले को वृक्ष मित्र बनाया जाएगा। 2 हजार वृक्ष मित्र बनाए जाएंगे जिन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य बहुत महान है हमें अपने पर्यावरण को बचाना है उसे सुरक्षित करना है। इसलिए जितने उत्साह और जितनी तत्परता से हम पौधे लगा रहे हैं उन पौधों को जीवित रखने के लिए, उन पौधों को जीवित रखकर उन्हें बड़ा करने के लिए उससे भी अधिक उत्साह, तत्परता और परिश्रम की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि हम सब बड़ी जिम्मेदारी से इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री के हरियालो राजस्थान को संकल्पना को साकार करने की यात्रा के सहभागी बनेंगे।

–**रचना सिद्धा, सहायक जनसंपर्क अधिकारी**

योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे : राज्यपाल बागड़े

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बालोतरा पहुंचे, कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली

बालोतरा, (निर्सं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एक दिवसीय दौरे पर बालोतरा पहुंचे। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने पर पुलिस दल ने मार्च पास्ट की सलामी दी। इसके पश्चात राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए वंचितों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार इस प्रकार हो कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी लाभ पहुंचे और वास्तविक जरूरतमंद वर्य सशक्त हो सके।

राज्यपाल ने योजनाओं के समयबद्ध और परिणामोन्मुखी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। इस दौरान राज्यपाल ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आवास योजना एवं अन्य योजनाओं का लाभ



बालोतरा में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

प्राथमिकता से देने को कहा। बैठक के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, मनरेगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, कुसुम योजना, मिशन हरियालो राजस्थान, राजीविका, डेयरी विकास एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि बच्चों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता

राजीविका, डेयरी विकास एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल देते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि बच्चों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता

को एक साथ विकसित किया जाए। उन्होंने जिले के स्कूलों में खेल मैदानों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और छात्रावासों में न्यायामशाला एवं खेल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा। राज्यपाल बागड़े ने ‘मिशन हरियालो राजस्थान’ की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहा जाए, बल्कि उनकी सुरक्षा और सार-संभाल भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कम जल आवश्यकता वाले पौधों के रोपण को प्राथमिकता देने को कहा ताकि पर्यावरणीय संतुलन के साथ जल संरक्षण भी संभव हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की समीक्षा करते हुए जल संचयन एवं भूजल स्तर बढ़ाने की दिशा में स्थानीय समाधान अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में वर्षा जल का संचयन उसी गांव में हो और वह व्यर्थ बहकर न जाए, इसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक ग्रामीण घर में शुद्ध पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित किया जाए। यह केंद्र सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक है और इसकी शत-प्रतिशत सफलता जरूरी है।

उन्होंने कहा कि राजीविका (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के तहत महिला समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग बढ़ाई जाए और प्रत्येक महिला को

उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाए। राज्यपाल बागड़े ने कृषि विभाग को मुदा परीक्षण कार्यक्रम के तहत अधिकतम किसानों को जोड़ने, वैज्ञानिक पद्धति से खेती को बढ़ावा देने, फार्म पॉन्ड निर्माण, फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण बढ़ाने और उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हेतु तकनीकी मार्गदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीस अपशिष्ट निस्तारण की भी समीक्षा करते हुए उन्होंने जैविक खाद निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा इसे किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे स्वच्छता के साथ कृषि को भी लाभ हो। राज्यपाल बागड़े ने अंत में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी योग्य नागरिक को योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाएं केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि धरातल पर नजर आएँ।

बैठक के दौरान जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक रमेश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. गुंजन सोनी, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, पंचपरदा विधायक डॉ. अरुण चौधरी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

राशिफल शुक्रवार 25 जुलाई, 2025



पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, पुष्य नक्षत्र सायं 4:01 तक, वज्र योग प्रातः 7:28 तक, किस्तुघ्न करण दिन 12:12 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क चन्द्रमा-कर्क, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज से नक्त व्रत आरम्भ होगा। आज जीवंतिका पूजन है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:32 तक, लाभ-अमृत 7:32 से 10:53 तक, शुभ 12:33 से 2:14 तक, चर 5:35 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:51, सूर्यास्त 7:15

 मेघ घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।	 सिंह घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। पारिवारिक व्यक्तित्गत कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।	 धनु चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में परेशानी हो सकती है। व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।
 वृष परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।	 कन्या आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।	 मकर परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
 मिथुन व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण-प्रभाव बढ़ेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।	 तुला व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।	 कुंभ व्यवस्था संबंधित चिन्ता दूर होगी। अनाहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।
 कर्क मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्यों योजनानुसार बनने लगेंगे। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 वृश्चिक नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटकें हूए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।	 मीन व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

विधान सभा में कारगिल वीरांगनाओं का सम्मान किया

कारगिल शौर्य वाटिका में शहीदों की याद में लगाये पौधे

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधान सभा का यह लोकतंत्र का पावन स्थल अब वीर शहीदों की शहादत की स्मृति में राष्ट्र प्रेरणा का तीर्थ भी बन गया है। अब यहां से वीरता की गुंज भी निकलेगी। देवनानी ने कहा कि जय हिन्द हमारे लिए गर्व का घोष है। राष्ट्र की रक्षा में अपने परिजनों को समर्पित करने वाली वीरांगनाएं समाज के लिए हाडी रानी हैं। इनके ऋण को तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन उनकी स्मृति को बनाये रखने और वीरांगनाओं का सम्मान करने का दायित्व हम सभी को मिलकर निभाना है।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी गुरुवार को राजस्थान विधान सभा में कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई) की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर देवनानी ने 21 वीरांगनाओं का शॉल ओढाकर और स्मृतिचिन्ह भेंट कर सम्मान किया। देवनानी ने इस अवसर पर विधान सभा परिसर में शहीदों की शहादत की अमिट स्मृति के लिए बनाई गई कारगिल शौर्य



देवनानी (बीच में) ने विधान सभा परिसर में बनाई गई कारगिल शौर्य वाटिका का पट्टिका अनवारण कर उद्घाटन किया।

वाटिका का पट्टिका अनवारण कर उद्घाटन किया। देवनानी ने कारगिल शौर्य वाटिका में वीरांगनाओं के साथ सिंदूर का पौधा रोपा। विधान सभा में हरियाली अमावस्या पर आयोजित इस राष्ट्रभक्ति समारोह के तहत राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण ने भी वीरांगनाओं के साथ वाटिका में सिंदूर, एरिका पाम, सांग ऑफ इण्डिया, किसना फाइकस और क्रोटीन प्रजाति के एक हजार एक सौ पौधे लगाए। देवनानी ने कहा कि विधानसभा परिसर में निर्मित यह वाटिका प्रत्येक जनप्रतिनिधि को

किसी क़ानून पर हस्ताक्षर करते समय याद दिलाएगी कि वीर शहीदों के कारण ही राष्ट्र और संविधान की रक्षा संभव है। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर लड़ा गया कारगिल युद्ध आत्मबल, राष्ट्रभक्ति और त्याग का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है। यहां के कण-कण में शौर्य गुंजता है। हम हाडी रानी के वंशज हैं जिन्होंने अपने वीर पति को युद्ध भूमि में अपना कटा शीश भेज दिया था। हमस्त वीरांगनायें हमारे लिये हाडी रानी ही है।सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन

■ देवनानी ने कारगिल शौर्य वाटिका में वीरांगनाओं के साथ सिंदूर का पौधा रोपा

राठौड ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण और वीरांगनाओं का सम्मान के लिए विधान सभा अध्यक्ष देवनानी की सोच सम्मानीय है।

उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं के सम्मान की जिम्मेदारी हम सभी की है। विशेषकर जिस गांव में वीरांगना निवास कर रही है, वहां के लोगों की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। राठौड ने कहा कि कारगिल अनोखा युद्ध था। इस युद्ध में भारतीय सेना का विपरित परिस्थितियों में विजयी होना अभूतपूर्व है। शौर्य वाटिका का निर्माण अभूतपूर्व पहल- वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में शौर्य वाटिका का निर्माण अभूतपूर्व पहल है। यह वाटिका प्रकृति संरक्षण में योगदान के साथ-साथ शहीदों की स्मृति का पावन स्थल भी बन गई है।

बैठक आयोजित “लहरिया उत्सव” का रंगारंग आयोजन छह अगस्त को

जयपुर । सरकार के आदेशों की अनुपालना में गुरुवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में नगरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली, समावेशी बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के नगरीय निकायों के पुनर्गठन एवं पुनर्समींकन से जुड़े प्रस्तावों पर गहन परीक्षण और विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सुरेश सिंह रावत, संजय शर्मा, गौतम कुमार तथा झावर सिंह खरा द्वारा इस बैठक में पुनर्समींकन के प्रस्तावों पर समीक्षा एवं विचार विमर्श किया गया।

“लहरिया उत्सव” का रंगारंग आयोजन छह अगस्त को

जयपुर। नृत्यम फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध समाज सेविका काजल सैनी के नेतृत्व में इस वर्ष का "लहरिया उत्सव" बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाएगा । यह सांस्कृतिक उत्सव छह अगस्त को स्वेज फार्म स्थित हीरा वैली रिसोर्ट में होगा। जिसमें महिलाओं और युवतियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

नृत्यम फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध समाज सेविका काजल सैनी ने बताया कि "लहरिया उत्सव" में डांस

प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, फैशन शो और कई अन्य सांस्कृतिक आकर्षण प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मानित अतिथि गणों द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना और उन्हें एक रचनात्मक मंच प्रदान करना है। सैनी ने बताया कि इस वर्ष की थीम "लहरिया" रखी गई है, जो राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति और सावन की उमंग को दर्शाती है। इस थीम के तहत महिलाएं रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधानों में लहरिया संगीत और गीतों

पर नाचती-झूमती नजर आएंगी, जो कार्यक्रम की शोभा को और भी बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम से पूर्व सभी प्रतिभागियों को पांच दिवसीय डांस ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके माध्यम से वे अपनी प्रस्तुति को और भी प्रभावशाली बना सकेगीं। यह प्रशिक्षण छह अगस्त को मंचित होने वाली प्रस्तुतियों का हिस्सा होगा।

काजल सैनी ने बताया कि "सावन सिर्फ ऋतु नहीं, एक उत्सव है भावनाओं का, रचनात्मकता का और नारी शक्ति के उत्साह का।

कृत्रिम गर्भाधान में पिछड़े 10 जिलों के लिये योजना बनाई

जयपुर। गर्भाधान में पिछड़े राजस्थान के 10 जिलों के लिए पशुपालन विभाग ने विशेष योजना बनाई है। इसके तहत केंद्र सरकार को 40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव को लेकर राजस्थान सरकार के

पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह से भेंट की। कुमावत ने केंद्रीय मंत्री को राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं नवाचारों की जानकारी दी। कुमावत ने विभाग द्वारा अब तक किए गए उल्लेखनीय कार्यों का संकलन 'प्रगति पुस्तिका' के रूप में भेंट कर केंद्रीय मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने राजस्थान के लिए पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं, योजनाओं में केंद्रीय अंश बढ़ाने तथा भावी सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की एवं संबंधित मांगों उनके समक्ष प्रस्तुत की।

जोराराम कुमावत ने बताया कि राज्य के 10 जिलों – बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, टोंक, राजसमन्द, पाली, त

■ उन्नत नस्ल सुधार के लिए राजस्थान को मिलेगी ब्राजील नसल के सांड के सीमन की डोज

प्रतापगढ़, सिरोही, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज 10 प्रतिशत से कम है इनमें एआई हेतु आवश्यक संसाधनों के स्ट्रैटेजिंग के लिए एक विशेष परियोजना भारत सरकार को राशि 40 करोड़ की स्वीकृति हेतु भेजी गई है । इसकी स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है ।

कुमावत ने बताया कि गिर गाय में उन्नत नस्ल सुधार के तहत राजस्थान को गिर गाय में एआई के लिए केंद्र सरकार से 2380 डोजेज की माँग की गई है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को प्रस्ताव सौंपा गया है । उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत राजस्थान को ब्राजील नसल के सांड का सीमन गिर गाय को लगाया जाएगा। इससे गिर गाय के दूध की मात्रा बढ़कर 40 से 50 लीटर तक हो जाएगी।

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, पाली लोकसभा से सांसद एवं वन नेशन, वन इलेक्शन पर गठित संयुक्त संसदीय समिति () के चेयरमैन पी. पी. चौधरी से भी शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर कुमावत ने उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करती पुस्तिका भी केंद्रीय मंत्री को भेंट की। कुमावत ने पी. पी. चौधरी से पाली लोकसभा सहित राजस्थान से जुड़े विभिन्न जनहित के विषयों पर सार्थक चर्चा की । मंत्री जोराराम कुमावत ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान बीकानेर हाउस में 30 जुलाई तक चलने वाले तीजोत्सव और हस्तशिल्प मेले का अवलोकन किया। इस दौरान कुमावत ने कहा कि राजस्थानी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए ऐसे मेले मिल का पत्थर साबित हो सकते हैं।

आर.यू.एच.एस. को रिम्स के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस) को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवरसर ने आरयूएचएस परिसर में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

खींवरसर ने बताया कि राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने अधिकारियों से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों को शीघ्रता से जारी करवाने और निविदा प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिम्स का विकास जयपुर सहित पूरे प्रदेश के नागरिकों के लिए उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शोध के नए द्वार खोलेगा।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि रिम्स का विकास तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ कर सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं का विस्तार, दूसरा

सेवानिवृत्त महिला व्याख्याता को 3.5 वर्ष का बकाया वेतन व सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा

राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह डॉ. कृष्णा जैन, पूर्व व्याख्याता (राजनैति विज्ञान), मीरा गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ को जनवरी 2016 से लेकर जुलाई 2019 तक का बकाया वेतन तथा समस्त सेवानिवृत्ति लाभ तीन माह की अवधि में अदा करे। यह निर्णय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया।

याचिकाकर्ता डॉ. कृष्णा जैन की ओर से अधिवक्ता सार्धक रस्तोगी ने पेरवै की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता आदित्य सिंह उपस्थित हुए। याचिका में यह कहा गया था कि

60 लाख की मादक पदार्थ स्मैक सहित तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने मुहाना थाना इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 256 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक सहित परिवहन में प्रयुक्त एक बिना नम्बरी बाइक भी जब्त की है। पुलिस के अनुसार जब्त की गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपये आंकी है। फिलहाल आरोपित तस्कर से पूछताछ की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध) रियाल सिंह ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सीएसटी ने मुहाना थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले प्रिंस मालावत (19) निवासी डिगंगी जिला टोंक हाल मुहाना जयपुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की तलाशी में उसके पास 256 ग्राम स्मैक मिली है।

डॉ. जैन को वर्ष 1983 में मीरा गर्ल्स कॉलेज में नियमित चयन के आधार पर व्याख्याता (राजनैति विज्ञान) के पद पर नियुक्त किया गया था, जो उस समय एक अनुदानित महाविद्यालय था और राज्य सरकार से 70प्रतिशत अनुदान प्राप्त करता था।

वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने इस कॉलेज को अधिगृहित कर इसके प्रबंधन, चल-अचल संपत्तियाँ एवं समस्त दायित्व अपने अधीन ले लिए। हालांकि, बाद में इस अधिग्रहण को निरस्त करने का प्रयास किया गया, जिसे न्यायालय ने अवैध ठहराते हुए निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता जुलाई 2019 में सेवानिवृत्त हो गईं, किंतु उन्हें दिसंबर

2015 के बाद का वेतन, पेंशन, ग्रेज्युटी, लीव एनकैशमेंट, वेतन पुनर्निर्धारण, चयन वेतनमान आदि आज तक नहीं दिए गए। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि एक बार जब राज्य सरकार ने कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इस अधिग्रहण को वैध ठहरा दिया गया, तो उस संस्था के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी भी सरकार की ही मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक स्वीकृत एवं अनुदानित पद पर कार्यरत थीं, और उनकी सेवा 2013 के आदेश के तहत राज्य सरकार द्वारा मानी गई थी। इसलिए राज्य सरकार उन्हें उनके सेवानिवृत्ति तक की समस्त देनदारियों के भुगतान की

जिम्मेदारी से इंकार नहीं कर सकती। यदि राज्य सरकार यह मानती है कि कॉलेज का प्रभावी अधिग्रहण 2020 में हुआ, तब भी कम-से-कम 70 प्रतिशत देनदारी तो उसकी बनती ही है और शेष 30 प्रतिशत वह कॉलेज प्रबंधन समिति से वसूल सकती है। न्यायालय ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2019 तक का वेतन, पेंशन, अवकाश नकदीकरण, चयन वेतनमान और सभी संशोधित वेतनमान के लाभा। इस अवधि के उपरांत भुगतान न होने पर बकाया वेतन पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा सेवानिवृत्ति लाभों पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।

कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात



जोराराम कुमावत (बांये) ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (दांये) से भी शिष्टाचार भेंट की।

■ बीकानेर हाउस में तीज मेले का भी किया अवलोकन

नवाचारों की जानकारी दी। कुमावत ने विभाग द्वारा अब तक किए गए उल्लेखनीय कार्यों का संकलन 'प्रगति पुस्तिका' के रूप में भेंट कर केंद्रीय मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने राजस्थान के लिए पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं, योजनाओं में केंद्रीय अंश बढ़ाने तथा भावी सहयोग

पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर लाठी-डंडों से हमला

जयपुर। जयपुर ग्रामीण जिले के चंदवाजी थाना इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर लाठी-डंडों से हमला करना का मामला सामने आया है। जो पहले पंप पर लूट की वारदात कर चुके थे। कर्मचारियों ने उन्हें पहचान लिया तो मौके से चले गए। फिर पेट्रोल पंप पर पहुंचकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। नकदी और सामान लूटकर भाग गए। हमले में सिस्कोरिटी गार्ड घायल हो गया। पुलिस फुटेज के आधार पर कार सवार हमलावरों की तलाश कर रही है।

थानाधिकारी हीरालाल सैनी ने बताया कि दिल्ली-अजमेर हाईवे पर चंदवाजी स्थित बीलपेट में पेट्रोल पम्प पर वारदात हुई। बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि तीन लड़के कार में डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पम्प पर आए थे।

पेट्रोल पम्प पर मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें पहचान लिया। करीब 15-20 दिन पहले बिना पेटेंट किए डीजल भरवाकर भागने की बात बताई। कार सवार लड़के झगड़ा कर धमकी देकर मौके से फरार हो गए। कार से उतरे चार-पांच लड़कों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

सहकारिता मंत्री ने की सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना की समीक्षा

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि किसानों को अधिक से अधिक राहत प्रदान करना राज्य सरकार का प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के बीमा के लिए व्यावहारिक विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे किसानों पर प्रीमियम का भार कम आए और उनके दावों का निस्तारण आसानी से हो सके।

दक गुरुवार को अपेक्स बैंक सभागार में सहकार जीवन रक्षा बीमा योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वित्त वर्षों में यह देखा गया है कि बीमा कम्पनियों द्वारा वसूले जाने वाले प्रीमियम और क्लेम की राशि में काफी अंतर होता है। बीमा कम्पनी द्वारा किसानों को किये जाने वाले दावों के भुगतान की राशि वसूले जाने वाले प्रीमियम की राशि की तुलना में बहुत कम होती है। अधिक प्रीमियम राशि के कारण किसानों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीमा कम्पनियों की मनमानी से बचाने तथा उन्हें आर्थिक राहत दिलाने के लिए एरिस्क रिलीफ फंड बनाया जाए।

ए.सी.बी. डीजी और प्रमुख खाद्य सचिव से मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत पर जांच की स्वीकृति नहीं देने से जुड़े मामले में एसीबी के डीजी और प्रमुख खाद्य सचिव सचिव अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पब्लिक ऑफ्ट करप्शन की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता टीएन शर्मा ने 7 सितंबर, 2021 को एसीबी में शिकायत दी थी। जिसमें कहा गया था कि खाद्य विभाग ने पीओएस मशीनों की खरीद व रखरखाव के लिए 135 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए। शिकायत में दो फर्मों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर हासिल करने का आरोप लगाया गया। याचिका में कहा गया कि एसीबी ने शिकायत दर्ज कर धारा 17ए के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए विभाग से स्वीकृति मांगी, लेकिन विभाग ने स्वीकृति नहीं दी। याचिका में कहा गया कि टेंडर लेने वाली फर्म में चीनी माल सप्लाई किया है और टेंडर की शर्तों की अवहेलना की गई। टेंडर शर्त के अनुसार पीओएस मशीनों की देखरेख के लिए फर्म को हर ब्लॉक व जिला स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति करनी थी,

■ जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश पब्लिक ऑफेंस्ट करप्शन की याचिका पर दिए

■ शिकायत में दो फर्मों पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर हासिल करने का आरोप लगाया

लेकिन फर्म ने कोई नियुक्ति भी नहीं की। इसके बावजूद भी मिलीभगत और षडयंत्र के तहत राज्य सरकार की ओर से इन दोनों फर्म को नियमित भुगतान किया जाता रहा। याचिकाकर्ता की ओर से एसीबी को कई बार इस संबंध में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन एसीबी ने मामले में कार्रवाई नहीं की। याचिका में कहा गया कि एसीबी को जांच की स्वीकृति के लिए विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद भी स्वीकृति नहीं मिलने का बहाना बनाकर मामले से परला झाड़ लिया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों के जवाब तलब किया है।

हरियालो राजस्थान अभियान में 27 जुलाई को हेरिटेज निगम 1.5 0 लाख पौधे लगाएगा

जयपुर। हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर तीज महोत्सव पर हेरिटेज निगम ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है। 27 जुलाई को हेरिटेज निगम निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कुलडेढ़ लाख पौधे लगाकर तीज महोत्सव मनाएगा।

- हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल की विशेष अपील**
- हेरिटेज निगम के प्रत्येक जोन में लगंगे 30 हजार पौधे लगाए जाएंगे**

इस आयोजन के लिए हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने सभी सहवासियों अपील भी की है। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने बताया कि राज्यभर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया जाएगा। इसी कड़ी में हेरिटेज निगम की ओर से डेढ़ लाख



आयुक्त निधि पटेल (दांये) ने निगम अधिकारी के साथ बैठक ली।

पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है। हेरिटेज निगम के प्रत्येक जोन में लगंगे 30 हजार पौधे लगाए जाएंगे।

आयुक्त निधि पटेल ने इस अभियान में निगम के सभी अधिकारी, स्वच्छता प्रहरी के साथ साथ व्यापार मंडल स्वयंसेवी संस्था, निजी संस्थान, मोहल्ला विकास समिति,

धार्मिक संगठनों, मीडिया संगठन को जुड़ने की अपील की है। उन्हों ए बताया कि हेरिटेज निगम के सभी पार्क में , शमशान घाट, कब्रिस्तान, गोशाला और अन्य सार्वजनिक जगहों पर पौधे लगाए जाएंगे।

आमजन निगम के पार्क के जाकर प्रकृति की रक्षा के लिए पौधे

लगा सकता है।

अभियान को सफल बनाने के लिए हेरिटेज निगम कि ओर से सभी 266 पार्क, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, सार्वजनिक स्थान, हिंगोनिया गोशाला पौधे रखवाएं का रहे है। 27 जुलाई को अभियान सुबह छह बजे से शुरू हो जाएगा।



युवक को गोली मारने के मामले में आरोपी विकास यादव (23) निवासी प्रागपुरा कोटपूतली बहरोड को गिरफ्तार किया

गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल नाबालिग साथी को भी पकड़ा है। लूट व हत्या के प्रयास में शामिल उनके साथी मोनू धनकड़ और जसरज गुर्जर उर्फ जस्सी की तलाश की जा रही है। पुलिस टीमें फरार साथियों को पकड़ने के लिए दबिश देने के साथ ही पकड़े गए आरोपियों से वारदात में यूज अवैध देसी कट्टे की बरामदगी के प्रयास कर रही है। पुलिस ने वारदातस्थल पर छोड़कर भागी बिना नंबर की स्विफ्ट कार को पहले

ही जब्त कर लिया था। जबड़ गए बदमाशों से पूछताछ में सामने आया कि शौक के लिए लूट की वारदात करने चारों साथी कार लेकर निकले थे। 18 जुलाई की रात करीब 12 बजे गांधी नगर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी युवती से मोबाइल छीन लिया। कार से भागते समय शाहिद के गट्टे वाले बाबा की दरगाह के पास आगे रोड बंद होने पर रुक गए। पीछा कर रहे कार सवार के पकड़ने आने पर देसी कट्टा निकालकर फायर किया।

मुख्यमंत्री ने बीसलपुर व नवनेरा बाँध भरने पर खुशी जताई

उन्होंने कहा कि मानसून में अच्छी बारिश से नियमित जलपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी

जयपुर, 24 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीसलपुर बांध का पूरा भरना अत्यंत हर्ष का विषय है। यह पहली बार है जब जुलाई माह में बीसलपुर बांध का गेट खोला गया है। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक

और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि 24 जुलाई 2025 की तारीख ने प्रदेश में नया इतिहास रचा है। बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पहली बार लगातार दो साल बीसलपुर बाँध पूरा भरा है। इस बाँध से जयपुर, अजमेर व टोंक जिले की करीब एक करोड़ की आबादी को पेयजल आपूर्ति की जाती है।**

परियोजना के घटक नवनेरा बांध (इटवा, कोटा) का भरना भी जलापूर्ति के साथ ही कृषि कार्यों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी अंचलों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं तथा इंदिरा गांधी नहर एवं गंगनहर के माध्यम से किसान सहित सभी वर्गों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि मानसून में अच्छी बारिश होने से निर्बाध

पानी का स्तर बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर तक पहुंच गया। इसके बाद गेट नंबर 10 को 1 मीटर खोल दिया गया, जिससे लगभग 6000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जुलाई में ही बीसलपुर बांध भर गया है। साथ ही, यह पहली बार है कि लगातार दो वर्ष (2024–2025) बीसलपुर बांध भरा है। गौरतलब है कि यह बांध परियोजना जयपुर, अजमेर एवं टोंक जिले की लगभग एक करोड़ आबादी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

वहीं नवनेरा बांध भी गुरुवार को



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

पूरा भर गया। इसमें पानी का लेवल 214 आरएल मीटर पहुंच गया जिसके बाद इसके गेट नंबर 11, 12 व 13 खोल दिए गए। इससे 600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस निकासी से अपस्ट्रीम में कालीसिंह नदी

कल तक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यादव, तेजस्वी यादव और अन्य नेता, इस पूरे घटनाक्रम को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। सभी को लग रहा है कि मतदाताओं को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना और इस तरह चुनाव को चुराना, लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है।

संसद के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसके बाद से फोकस लगातार बिहार और एस आई आर मुद्दे पर बना हुआ है।

विपक्ष रोजाना संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहा है और कल वे गांधी प्रतिमा से संसद के मकर द्वार तक मार्च करेंगे।

सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि विपक्ष को आपत्ति है, तो वह चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट जाए।

अब यह विपक्ष पर निर्भर है कि वह लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेगा और उन तरीकों का विरोध कैसे करेगा, जिनके जरिए संविधान की अनदेखी करके, दिन-दहाड़े चुनावों में सेंध लगाई जा रही है तथा उन्हें प्रभावित किया जा रहा है।

आज निर्णय होगा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंतरिम रोज़े जारी रहनी चाहिए? पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति क्रांत ने कहा, हम कल 10-15 मिनट और लेंगे और मामले को निपटारा कर देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने मुम्बई ट्रेन धमाकों पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, 24 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी सभी 12 लोगों को बरी करने के बम्बई उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के फैसले पर गुरुवार को रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को उस याचिका

■ **लेकिन हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए सभी 12 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।**

को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के फैसले को अन्य लॉबिंग महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामलों में मिसाल नहीं माना जाए। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर संबंधित सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने इस दलील पर गौर किया और स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल नहीं माना जाएगा।

केन्द्र सरकार को संवैधानिक पदों , संस्थाओं व संविधान की परवाह नहीं- पायलट

सचिन पायलट ने टोंक में धन्ना तलाई के ड्रेनेज सिस्टम व सौन्दर्यीकरण का शिलान्यास किया



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने गुरुवार को टोंक में डेढ़ करोड़ रुपये के पानी निकासी के ड्रेनेज सिस्टम एवं सौन्दर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया।

संविधान की कोई परवाह नहीं है।

करने का काम भाजपा सरकार ने किया है।

पायलट ने डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से टोंक शहर स्थित धन्ना तलाई

भाजपा से नाराज़ हिंदू वोटों पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के रूप में देखा जाता है। ऐसे में, अखिलेश यादव ने अपने मंदिर के वीडियो को पोस्ट करना बेहतर समझा, तथा इस बहाने पहले ही साबित कर दिया था। हालांकि यादव ने हाल ही में सांपट हिंदुत्व की ओर कदम बढ़ाया है, लेकिन उन्हें हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों से पहले ही आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

चूँकि इटावा का यह मंदिर जिसे 'केदारेश्वर धाम' नाम दिया गया है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से एक, 'केदारनाथ धाम' की तर्ज पर बन रहा है, इसलिये उत्तराखंड के संतों और साधुओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है।

उनका आरोप है कि मंदिर की नकल करना केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थस्थल की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इसे 'सनातन धर्म' के खिलाफ एक बड़ी साजिश' करार देते हुए कहा कि यह सदियों पुराने हिमालयी मंदिर की ऐतिहासिक धार्मिक महत्ता को कमजोर करने का प्रयास है।

हालांकि यादव ने इस आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन 2023 का एक पुराना वीडियो, जिसमें वे धार्मिक प्रवचनकर्ता अनिरुद्धाचार्य के साथ सड़क किनारे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, हाल ही में वायरल हुआ है। इस वीडियो के जरिए उनकी हिंदू संतों के

साथ कथित अभद्रता की आलोचना फिर से शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त, यादव की 'सांपट हिंदुत्व' रणनीति की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थापना से ही इसकी धर्मनिरपेक्ष पहचान रही है। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को अक्सर मुस्लिम तृष्टिकरण के रूप में देखा गया है-खासतौर पर उत्तर प्रदेश में।

समाजवादी पार्टी के गठन से पहले, जब सपा-संस्थापक मुलायम सिंह यादव जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अखिलेश यादव की वर्तमान धार्मिक मुद्रा की विश्वसनीयता को और कमजोर करती है।

‘क्या मृत मतदाताओं को भी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जोर देकर कहा कि हर मतदाते के लिए एक ज़रूरीहित और साफ-सुथरी मतदाता सूची तैयार चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है।

उन्होंने पूछा, “क्या पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की गई एक शुद्ध मतदाता सूची, निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं होती?” उन्होंने आगे कहा, “इन सवालों पर, कभी न कभी हम सभी को और भारत के सभी नागरिकों को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर गंभीरता से सोचना होगा।”

मुख्य चुनाव आयुक्त की ये टिप्पणियाँ ऐसे समय आई हैं जब विपक्षी दल, विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.) और

कांग्रेस, यह आरोप लगा रहे हैं कि एस.आई.आर. प्रक्रिया के कारण 50 लाख से अधिक लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

कुमार ने उसी संविधान का हवाला दिया, विपक्ष के अनुसार, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से कुचला जा रहा है।

ज्ञानेश कुमार ने कहा, “भारत का संविधान ही भारत के लोकतंत्र की जननी है। चुनाव आयोग को डर है कि अगर मृत लोगों के नाम पर, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम पर, डुप्लीकेट या फर्जी और विदेशी वोटरों के नाम पर वोट डाले गए, तो चुनाव प्रक्रिया भटक सकती है। इसीलिए यह

समीक्षा बिहार में शुरू की गई है और इसे पूरे देश में ले जाया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा। “क्या चुनाव आयोग को ऐसे मतदाताओं को सूची से नहीं हटाना चाहिए?” चुनाव आयोग के द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार की मतदाता सूची से 56 लाख नाम हटाए जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन 56 लाख नामों में शामिल हैं: 20 लाख मृतक मतदाता, 28 लाख अन्य राज्य में स्थायी रूप से चले गए लोग, 7 लाख ऐसे लोग जो एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं और 1 लाख ऐसे मतदाता जिनसे संपर्क नहीं हो सका। इसके अलावा, लगभग 15 लाख लोगों ने सत्यापन फॉर्म वापस नहीं किया, जिससे उनकी स्थिति भी संदेह में आ गई है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हालांकि यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। सेवाएं-जो भारत के लिए एक प्रमुख क्षेत्र हैं, भी इसका बड़ा लाभ उठाएंगी। एफटीए के आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, वास्तुकला और परामर्श सेवाओं के लिए भारतीय कंपनियों के ब्रिटेन में प्रवेश नियमों में ढील दी गई है। वहीं, ब्रिटिश सेवा प्रदाताओं को भारत के मध्यम वर्ग द्वारा संचालित सेवा अर्थव्यवस्था तक सुनिश्चित पहुंच मिलेगी।

एक ऐतिहासिक प्रावधान एक लंबे समय से चली आ रही भारतीय चिंता को दूर करता है, यूके में कार्यरत भारतीय पेशेवरों द्वारा सामाजिक सुरक्षा भुगतान। इस समझौते के तहत, ऐसे पेशेवर अब तीन वर्षों तक इन भुगतानों से मुक्त रहेंगे, प्रत्येक कर्मचारी के लिए हजारों पाउंड की संभावित वार्षिक बचत।

हालांकि यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। सेवाएं-जो भारत के लिए एक प्रमुख क्षेत्र हैं, भी इसका बड़ा लाभ उठाएंगी। एफटीए के आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, वास्तुकला और परामर्श सेवाओं के लिए भारतीय कंपनियों के ब्रिटेन में प्रवेश नियमों में ढील दी गई है। वहीं, ब्रिटिश सेवा प्रदाताओं को भारत के मध्यम वर्ग द्वारा संचालित सेवा अर्थव्यवस्था तक सुनिश्चित पहुंच मिलेगी।

एक ऐतिहासिक प्रावधान एक लंबे समय से चली आ रही भारतीय चिंता को दूर करता है, यूके में कार्यरत भारतीय पेशेवरों द्वारा सामाजिक सुरक्षा भुगतान। इस समझौते के तहत, ऐसे पेशेवर अब तीन वर्षों तक इन भुगतानों से मुक्त रहेंगे, प्रत्येक कर्मचारी के लिए हजारों पाउंड की संभावित वार्षिक बचत।

हालांकि यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। सेवाएं-जो भारत के लिए एक प्रमुख क्षेत्र हैं, भी इसका बड़ा लाभ उठाएंगी। एफटीए के आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, वास्तुकला और परामर्श सेवाओं के लिए भारतीय कंपनियों के ब्रिटेन में प्रवेश नियमों में ढील दी गई है। वहीं, ब्रिटिश सेवा प्रदाताओं को भारत के मध्यम वर्ग द्वारा संचालित सेवा अर्थव्यवस्था तक सुनिश्चित पहुंच मिलेगी।

उनका आरोप है कि मंदिर की नकल करना केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थस्थल की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इसे 'सनातन धर्म' के खिलाफ एक बड़ी साजिश' करार देते हुए कहा कि यह सदियों पुराने हिमालयी मंदिर की ऐतिहासिक धार्मिक महत्ता को कमजोर करने का प्रयास है।

हालांकि यादव ने इस आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन 2023 का एक पुराना वीडियो, जिसमें वे धार्मिक प्रवचनकर्ता अनिरुद्धाचार्य के साथ सड़क किनारे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, हाल ही में वायरल हुआ है। इस वीडियो के जरिए उनकी हिंदू संतों के

साथ कथित अभद्रता की आलोचना फिर से शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त, यादव की 'सांपट हिंदुत्व' रणनीति की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थापना से ही इसकी धर्मनिरपेक्ष पहचान रही है। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को अक्सर मुस्लिम तृष्टिकरण के रूप में देखा गया है-खासतौर पर उत्तर प्रदेश में।

समाजवादी पार्टी के गठन से पहले, जब सपा-संस्थापक मुलायम सिंह यादव जनता दल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अखिलेश यादव की वर्तमान धार्मिक मुद्रा की विश्वसनीयता को और कमजोर करती है।

नाबालिग का देह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईमेल कर अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दी थी। इस पर वह झोटावाड़ा स्थित अपनी दुकान से घर चला गया। जहां पीड़िता ने उसे बताया कि अभियुक्त उसे डरा धमकाकर आए दिन दुष्कर्म करते थे। इसके बाद, शाम के समय पीड़िता ने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की, लेकिन समय पर पता चलने पर उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, पीड़िता ने अदालत को बताया कि शैतान का शराब का ठेका उसके घर के पास होने के कारण वह उसे जानती थी। शैतान ने 9 मई 2018 को उसे नौद की गोलियां देकर, परिजनों को देने को कहा। रात के समय उसने परिजनों को नौद की गोलियां दीं और शैतान से मिलने उसके वहाँ चली गई।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गतिशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामान, सेवाओं और डिजिटल व्यापार के प्रवाह को फिर से आकार देने वाला एक रणनीतिक सहयोग है।

एफटीए का मूल उद्देश्य है शुल्कों को अभूतपूर्व स्तर पर कम करना। अब भारत से 99 प्रतिशत निर्यात ब्रिटेन में बिना शुल्क के प्रवेश करेंगे, जिससे वस्त्र, रत्न और आभूषण, जूते, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग उत्पादों और मशीनरी जैसे क्षेत्रों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय निर्यातकों के लिए इसका मतलब है उच्च-मूल्य वाले ब्रिटिश बाजारों तक लगभग त्वरित पहुंच, वह भी पहले जैसी लातत बाधाओं के बिना। कपड़ा उद्योग, जो पहले से ही बड़े पैमाने पर रोजगार देता है, इस समझौते से सबसे अधिक लाभ उठाने वालों में से एक होगा,

साथ ही भारत के एमएसएमई और समुद्री उत्पाद निर्यातक भी लाभान्वित होंगे।

बदले में, भारत ब्रिटेन से आने वाले 90 प्रतिशत उत्पादों पर आयात शुल्कों का कटौत करेगा, जिससे भारतीय उद्योगिका बाजार में प्रीमियम कारों, दवाओं, स्कॉच व्हिस्की और उच्च गुणवत्ता वाली कार्रलेट जैसे ब्रिटिश उत्पादों के लिए रास्ता खुलेगा। स्कॉच व्हिस्की और जिन जैसी ब्रिटिश वस्तुओं पर वर्तमान में 150 प्रतिशत टैक्स लगता है, जिसे तुरंत घटाकर 75 प्रतिशत और अगले दस वर्षों में 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इसी तरह, ब्रिटिश लज़री कारों पर 100 प्रतिशत से अधिक आयात शुल्क लगता था, इसे घटाकर मात्रा 10 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

हालांकि यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। सेवाएं-जो भारत के लिए एक प्रमुख क्षेत्र हैं, भी इसका बड़ा लाभ उठाएंगी। एफटीए के आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, वास्तुकला और परामर्श सेवाओं के लिए भारतीय कंपनियों के ब्रिटेन में प्रवेश नियमों में ढील दी गई है। वहीं, ब्रिटिश सेवा प्रदाताओं को भारत के मध्यम वर्ग द्वारा संचालित सेवा अर्थव्यवस्था तक सुनिश्चित पहुंच मिलेगी।

एक ऐतिहासिक प्रावधान एक लंबे समय से चली आ रही भारतीय चिंता को दूर करता है, यूके में कार्यरत भारतीय पेशेवरों द्वारा सामाजिक सुरक्षा भुगतान। इस समझौते के तहत, ऐसे पेशेवर अब तीन वर्षों तक इन भुगतानों से मुक्त रहेंगे, प्रत्येक कर्मचारी के लिए हजारों पाउंड की संभावित वार्षिक बचत।

हालांकि यह समझौता केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है। सेवाएं-जो भारत के लिए एक प्रमुख क्षेत्र हैं, भी इसका बड़ा लाभ उठाएंगी। एफटीए के आईटी, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, वास्तुकला और परामर्श सेवाओं के लिए भारतीय कंपनियों के ब्रिटेन में प्रवेश नियमों में ढील दी गई है। वहीं, ब्रिटिश सेवा प्रदाताओं को भारत के मध्यम वर्ग द्वारा संचालित सेवा अर्थव्यवस्था तक सुनिश्चित पहुंच मिलेगी।

एक ऐतिहासिक प्रावधान एक लंबे समय से चली आ रही भारतीय चिंता को दूर करता है, यूके में कार्यरत भारतीय पेशेवरों द्वारा सामाजिक सुरक्षा भुगतान। इस समझौते के तहत, ऐसे पेशेवर अब तीन वर्षों तक इन भुगतानों से मुक्त रहेंगे, प्रत्येक कर्मचारी के लिए हजारों पाउंड की संभावित वार्षिक बचत।

15 महीनों में इसके लागू होने की उम्मीद है।

यह समझौता केवल एक आर्थिक सुधार नहीं है, बल्कि यह एक साहसिक भू-राजनीतिक वक्तव्य है। जब वैश्विक व्यापार साझेदारियों का पुनर्गठन हो रहा है, भारत और ब्रिटेन एक-दूसरे के भविष्य पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र ने इस एफटीए का जोरदार स्वागत किया है और इसे भारत के उभरते व्यापार ढांचे में एक प्रमुख मील का पत्थर बताया है, जो वैश्विक आर्थिक एकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है।

आरपीजी ग्रुप के वाइस चेयरमैन अनंत गोयनका ने कहा, “भारत-ब्रिटेन एफटीए दोनों देशों के बीच साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह समझौता व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है और भारतीय निर्यातकों के लिए बेहतर

कार्यालय : पलायन हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फ़ैक्स: 0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फ़ैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हट्टा, बीकानेरा फोन: 2200660, फ़ैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फ़ैक्स: 02973-226424 **हिण्डोजनसिटी कार्यालय** :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोजनसिटी। फोन: 230200, 230400, फ़ैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय** : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फ़ैक्स: 01562-256908

■ **कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, भाजपा सरकार मनरेगा योजना की प्रक्रिया को इतना जटिल बना रही है कि लोग इससे जुड़ ही नहीं पायें।**

के पानी की निकासी के ड्रेनेज सिस्टम एवं सौन्दर्यीकरण कार्य का शिलान्यास तथा विधायक मद से 10 लाख रुपये की राशि से वार्ड नं. 56 में बने सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते हुए कहा कि धन्ना तलाई में आज जो विकास कार्य का शिलान्यास किया है, इस कार्य के पूर्ण होने पर यहां के लोगों को गंदे पानी से निजात मिलेगी और यहां एक सुन्दर पार्क विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज तथा न्यू हॉस्पिटल का कार्य शीघ्र पूर्ण होने वाला है। इससे टोंक व आसपास के लोगों को इलाज के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो विकास के कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी।

आमतौर से ऐसा माना जाता है कि जनता की स्मृति अल्पकालिक होती है और दशकों पुराने विवादों का चुनावी प्रभाव कम हो जाता है, फिर भी हाल ही में संसद मार्ग पर स्थित एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ अखिलेश यादव की बैठक ने उनकी 'सांपट हिंदुत्व' नीति की ईमानदारी पर नये सिर से संदेह पैदा कर दिये हैं।

यादव के 'हिंदुत्व' ब्रांड के लिये सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो पहले से ही एक शक्तिशाली हिंदुत्व प्रतीक के रूप में स्थापित हैं तथा इस प्रकार, समाजवादी पार्टी के लिए इस क्षेत्र में विस्तार की गुंजाइश सीमित दिखाई देती है।

उम्मीद करते हैं।” फिक्की के अध्यक्ष और इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एवं एमडी, हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा, “भारत-यूके एफटीए पर हस्ताक्षर करने के व्यापार ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो वैश्विक आर्थिक एकीकरण के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। यह आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों का पूरक है, जिससे घरेलू उद्योग वैश्विक स्तर पर विस्तार कर सकें, प्रतिस्पर्धा बन सकें और मूल्य श्रृंखलाओं का अधिक प्रभावी तरीके से लाभ उठा सकें। फिक्की इस विकास का स्वागत करता है, जो एक अधिक लचीला और अक्सर प्रधान व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक कदम है, जिससे दोनों देशों और उनके नागरिकों को लाभ होगा।”